क्र०स०	राष्ट्रीयकृत बैंकों का नाम	उपकार्यालय का नाम (जिला सहित)
	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	
1.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	बाजना (रतलाम)
2.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	मनसा (मनसोर)
3.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	सुवासरी (मवसोर)
4.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया (भारतीय स्टेट बैंक)	राहाली (सागर)
5.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	बान्दा (सागर)
6.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	उदयपुर (रायसेन)
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया (यूको बैंक) (भारतीय स्टेट बैंक)	बरेली (रायसेन)
8.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	गरतगंज (रायसेन)
9.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	गोहारगंज (रायसेन)
10.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया (भारतीय स्टेट बैंक)	पटल (जबलपुर)
11.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	अमरवाड़ा (चिदवाड़ा)
12.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया (भारतीय स्टेट बैंक)	परसिया (चिदवाड़ा)
13.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	लखनदोन (शहनी)
14.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	सारीपल्ली (रायपुर)
15.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	पुष्पराजगढ (शाडोल)
	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया (भारतीय स्टेट बैंक)	ब्योहारी (शाडोल)

सहकारी बैंकों के लिए नई योजनाएं

2736. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय द्वारा वाणिज्यिक और ग्रामीण बैंकों के समान सहकारी बैंकों के पूंजी आधार को सुदृढ़ करने के लिए कोई योजना बनाई गई है; यदि हां तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या वित्त मंत्रालय उक्त प्रस्ताव पर अब विचार-विमर्श करने का विचार रखता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वीरप्पा मोइली): (क) से (ग) सहकारी संस्थाएं चूंकि राज्य का विषय है इसलिए सहकारी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को अपनी भूमिका अदा करने होती है। सहकारी बैंकों के संसाधन आधार को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बातों के साथ-साथ इस उद्देश्य के लिए स्थापित राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम प्रदान करता रहा है ताकि वे सहकारी ऋण समितियों की शेयर पूंजी में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अंशदान कर सकें। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना के बाद इस निधि को नाबार्ड को स्थानांतरित कर दिया गया है। अब इस निधि को राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (एल टी ओ) के रूप में जाना जाता है। नाबार्ड सहकारी ऋण समितियों की शेयर पूंजी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देने के लिए उन्हें सहायता देने के लिए निधि में से राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम दे सकता है। शेयर को सम्बद्ध करना सहकारी क्षेत्र में उच्च स्तर की पूंजी आधार की वृद्धि को सुनिश्चित करता है।